



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]
No. 100]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2003/आषाढ़ 2, 1925
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2003/ASADA 2, 1925

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2003

फा. सं. फ. 48-6/2003-राअशिप(एन एण्ड एस).-- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वाँ) की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सेंट जान टीचर्स ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट की 2001 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 2421 तथा इसी प्रकार की विशेष अनुमति याचिकाओं के एक समूह और रिट याचिकाओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7.02.2003 के निर्णय के अनुसरण में जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को अन्य बातों के साथ साथ ऐसे उपयुक्त विनियम बनाने के निदेश दिए गए हैं, जिनके अधीन ऐसी समय-सीमा निर्धारित की जाएगी जिसके भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए किसी संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना होगा, दिनांक 13 नवम्बर 2002 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का पपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 को संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन

- (i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का पपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) (संशोधन) विनियम 2003 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

संशोधन की सीमा

उपर्युक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियमों के पैरा 6 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(i) अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के निमित्त मान्यता प्रदान किए जाने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा अथवा कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने तथा/अथवा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में मौजूदा संस्थान के आवेदन पत्र के साथ, जिस स्थान पर वह स्थित है वहां की राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र की ओर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) संलग्न किया जाएगा । राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र के अनापत्ति प्रमाण-पत्र / समर्थन के बिना प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(ii) अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने अथवा कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने तथा / अथवा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में संस्थान के आवेदन पत्र का प्रत्येक राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र द्वारा यथासम्भव शीघ्र निपटान करने का प्रयास किया जाएगा और अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के निमित्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित अन्तिम तारीख के 6 महीने के भीतर उसे अपना अनापत्ति प्रमाण-पत्र / समर्थन प्रदान करना होगा ।

(iii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र पर विचार करते समय प्रत्येक राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा ।

(iv) मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय क्षेत्रीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र प्रशासन के अनापत्ति प्रमाण-पत्र / समर्थन पर विचार किया जाएगा ।

(v) राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र में, अध्यापक शिक्षा में सम्बन्धित सेवा-पूर्व पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मूल यूनिट की

अधिकतम सीमा के भीतर उन सीटों की संख्या निर्दिष्ट करेगा जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है और इस सूचना के न होने पर ऐसा मान लिया जाएगा कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के मूल यूनिट के लिए है।

(vi) राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र प्रशासन उसे वापिस / रद्द नहीं कर देती / देता।

(vii) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख के बाद तीन वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र को व्यपगत समझा जाएगा।

(viii) सरकारी संस्थानों के मामले में अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्त लागू नहीं होगी।

(ix) अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के लिए नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं, इस बात का निर्णय सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जाएगा।

एस.के. राय, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2003-असाधारण]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2003

F. No. F. 48-6/2003-NCTE (N&S).—In exercise of the powers conferred under clauses (f) and (g) of Sub-section (2) of Section 32 of the NCTE Act, 1993 (73 of 1993) and pursuant to the judgement dated 7-02-2003, of the Hon'ble Supreme Court in SLP© No. 2421 of 2001 in the matter of St. John Teachers Training Institute and a batch of similar Special Leave Petitions and Writ Petitions, interalia, directing NCTE to frame appropriate regulations fixing the time limit within which a decision should be taken by the State Government on the application made by an institution for grant of No Objection Certificate, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations to amend the NCTE (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 dated 13th November, 2002.

1 Short Title and Commencement

- (i) These regulations may be called the NCTE (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations, 2003.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2

Extent of Amendment

Para 6 of the aforesaid NCTE Regulations shall be substituted by the following:-

- (i) Application from every institution seeking recognition to start a course or training in teacher education or from an existing institution seeking permission to start a new course or training and/or increase in intake shall be accompanied by a No Objection Certificate (NOC) from the State or Union Territory in which the institution is located. Application without NOC/endorsement of the State Government / UT shall not be processed by the concerned Regional Committee of NCTE.
- (ii) Every State Government/ UT Administration shall endeavour to dispose of the application of the institution seeking NOC for starting a course or training in teacher education or seeking permission to start a new course or training and/or increase in intake, as expeditiously as possible, and shall provide its NOC/endorsement within six months of the last date of receipt of application for grant of NOC fixed by the concerned State Government/UT.
- (iii) Every State Government /UT Administration while considering application for grant of No Objection Certificate shall take into account the guidelines for issue of No Objection Certificate issued by the NCTE from time to time.
- (iv) The NOC/endorsement of the State Government/UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition.
- (v) The State Government/UT Administration will indicate in the NOC the number of seats for which NOC is being granted within the ceiling of basic unit fixed by the NCTE for the concerned pre-service course on teacher education and without this information it will be presumed that the NOC is for the basic unit of the course.
- (vi) The NOC issued by the State Government /UT Administration will remain valid till such time the State Government/UT Administration withdraws/cancels it.
- (vii) The NOC will deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition from NCTE for the course within three years from the date of its issue.
- (viii) Requirement of NOC shall not apply to Government institutions.
- (ix) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (Fifty only). The question as to whether a programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.

S. K. RAY, Member-Secy.

[ADVT. III/IV/131/2003-Exty.]